

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1263
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

विश्वविद्यालय टाउनशिप और शिक्षा से रोजगार संबंधी पहलों का क्रियान्वयन

†1263. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गलियारों के समीप पांच विश्वविद्यालय टाउनशिपों के विकास के लिए स्थानों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा और इसके लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;
- (ख) उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा के माध्यम से रोजगार और उद्यम संबंधी स्थायी समिति के प्रस्तावित गठन, अधिदेश, कार्यो और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम के ढांचे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग तथा कॉमिक्स (एवीजीसी) को एकीकृत करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके साथ ही युवाओं की रोजगार क्षमता पर इन पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रस्तावित प्रणाली क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने शिक्षा परिदृश्य को बहु-विषयक, समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को तैयार और अनुमोदित किया है। इसमें सभी के लिए शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें भौतिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल उपकरणों और कनेक्टिविटी के प्रावधान और अधिक उद्योग-शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया है।

एनईपी 2020 के परिकल्पना के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2026-27 में यह घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण भारत के प्रमुख औद्योगिक

और लॉजिस्टिक गलियारों के आस-पास करना है। इसका चुनाव केन्द्र सरकार चुनौती मार्ग से करेगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि जैसे संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

भारत को सेवाओं में वैश्विक अग्रणी बनाने और विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए, नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन करने और उसके उपायों का प्रस्ताव करने, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' से सम्बन्धित उच्चस्तरीय स्थायी समिति की स्थापना की भी घोषणा की गई है। समिति का संघटन **अनुलग्नक में है।**

एनईपी 2020 के अनुरूप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सीटी) को एकीकृत किया है। इस रूपरेखा के तहत वर्ष 2030 तक एआई-साक्षर शिक्षार्थियों के निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण से एआई को प्रस्तुत किया गया है जो कम्प्यूटेशनल सोच, डिजिटल साक्षरता, नवाचार, समस्या-समाधान और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र के लिए पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई की सहायता करके 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है।

'विश्वविद्यालय टाउनशिप और शिक्षा से रोजगार संबंधी पहलों का कार्यान्वयन' के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में अनुलग्नक

उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' संबंधी स्थायी समिति का संघटन

क्र.सं.	नाम और पदनाम	भूमिका
1.	सीईओ, नीति आयोग	सभापति
2.	सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
3.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
9.	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सदस्य
10.	मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
11.	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
14.	महानिदेशक, सीआईआई	सदस्य
15.	महानिदेशक, फिक्की	सदस्य
16.	एसजी, एफआईएसएमई	सदस्य
17.	अध्यक्ष, नैसकॉम	सदस्य
18.	महानिदेशक, एसईपीसी	सदस्य
19.	डॉ. ए. शक्तिवेल, तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक-अध्यक्ष	सदस्य
20.	डॉ. चंदन चौधरी, प्रोफेसर, आईएसबी	सदस्य
21.	डॉ. रजत कथूरिया, डीन, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, शिव नादर विश्वविद्यालय	सदस्य
22.	कार्यक्रम निदेशक (सेवाएं), नीति आयोग	सदस्य संयोजक